



● वर्ष : 63, अंक : 22

● उज्जैन, मंगलवार दिनांक 27-02-2024 से 04-03-2024 तक

● पृष्ठ : 08 ● मूल्य : 2 रुपये

सबसे अधिक आबादी वाला देश, भारत दुनिया में आशावाद की पेशकश कर रहा

क्यों भारत चीन की अर्थव्यवस्था का वास्तविक विकल्प प्रस्तुत करती है?

दुनिया भर के वित्तीय पेशेवर 2014 से भारत के विकास को देख रहे हैं और 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने को लेकर काफी आशावादी हैं। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश, भारत दुनिया भर में आशावाद की पेशकश कर रहा है, जबकि इसके विपरीत, चीन, जो असंख्य आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, देश से पूँजी की त्वरित उड़ान का संकेत दे रहा है।

दुनियाभर के वित्तीय पेशेवर भारत के विकास को देख रहे हैं 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 ट्रिलियन डॉलर की बनने को लेकर काफी आशावादी हैं

शेयर बाजार-भारत बनाम चीन
चीन के शेयर बाजारों को 2021 में हालिया शिखर के बाद से एक लंबी मंदी का सामना करना पड़ा है, जिसमें शंघाई, शेन्जेन और हांगकांग के बाजारों से 5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक बाजार मूल्य का सफाया हो गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में पिछले साल गिरावट आई और जनवरी में फिर से गिरावट आई, जो 2023 के इसी महीने की तुलना में लगभग 12% कम है। इस बीच, भारत का शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। भारत के एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध कंपनियों का मूल्य पिछले साल के अंत में \$4 ट्रिलियन से अधिक हो गया।

जेफरीज की रिपोर्ट (फरवरी 2024 में) के अनुसार-

भारत का भविष्य और भी उज्ज्वल दिखाई देता है। 2030 तक भारत का बाजार मूल्य दोगुना से अधिक 10 ट्रिलियन डॉलर होने की उम्मीद है, जिससे बढ़े वैश्विक निवेशकों के लिए इसे नजरअंदाज करना असंभव हो जाएगा।

भारत और MSCI सूचकांक

वैश्विक स्टॉक इंडेक्स खस्तृदू द्वारा नवीनतम संशोधन भारत के प्रति तेजी को दर्शाता है। खस्तृदू ने इस महीने कहा था कि वह अपने उभरते बाजारों के सूचकांक में भारत का भारांक 17.98% से बढ़ाकर 18.06% कर देगा, जबकि चीन का भारांक घटाकर 24.77% कर देगा।

MSCI के सूचकांक दुनिया भर के संस्थागत निवेशकों को यह तय करने में मदद करते हैं कि उन्हें पैसा कैसे आवंटित करना है और अपने शोध को कहाँ केंद्रित करना है।

कुछ साल पहले MSCI उभरते बाजार सूचकांक में भारत का वजन

लगभग 7% था और विशेषज्ञों द्वारा यह उम्मीद की जाती है कि वह 18% [MSCI सूचकांक में] स्वाभाविक रूप से अगले 5 वर्षों में 25% की ओर बढ़ रहा है।

अगला वैश्विक विकास इंजन

भारत भर में उत्साह के अच्छे कारण हैं। बढ़ती युवा आबादी से लेकर बढ़ती फैक्टरियों तक, देश के पक्ष में बहुत कुछ है। IMF (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) को उम्मीद है कि अगले वित्तीय वर्ष में भारत की विकास दर 6.5% रहेगी जबकि चीन की विकास दर 4.6% रहेगी। जेफरीज के विश्लेषकों को उम्मीद है कि देश 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत अभी बुनियादी ढांचे में बदलाव की शुरुआत में है, सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और रेलवे के निर्माण पर अरबों खर्च कर रहा है। डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे में निवेश से अर्थव्यवस्था पर बहुत मजबूत गुणक प्रभाव पड़ता है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था भी आपूर्ति श्रृंखलाओं (Supply) पर

कंपनियों के बीच चल रहे पुनर्विचार का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। वैश्विक व्यवसाय चीन से दूर परिचालन में विविधता लाना चाहते हैं, जहां उन्हें महामारी के दौरान बाधाओं का सामना करना पड़ा और बीजिंग और वाशिंगटन के बीच तनाव से उत्पन्न जोखिमों का सामना करना पड़ा। अर्थशास्त्री ह्यूबर्ट डी बारोचेज के

अनुसार-

भारत आपूर्ति श्रृंखलाओं की Friend Sharing से लाभ पाने का प्रमुख उम्मीदवार है, विशेष रूप से चीन की कीमत पर, परिणामस्वरूप, Apple / Fo&con सहित दुनिया की

कुछ सबसे बड़ी कंपनियां अपने supplies का विस्तार कर रही हैं भारत में। Tesla के सीईओ एलोन मस्क ने पिछले जून में कहा था कि उनकी कंपनी जितनी जल्दी संभव हो सके भारत में निवेश करना चाहती है। क्या यह प्रचार के लायक है?

जबकि दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में रुचि बढ़ रही है, भारत के शेयरों की ऊंची कीमतें कुछ अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को डरा रही हैं। अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारतीय शेयर हमेशा महंगे रहे हैं, लेकिन अब प्रीमियम पर प्रीमियम का विस्तार हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू निवेशक, खुदरा और संस्थागत दोनों, इन उच्च मूल्यांकन को दरकिनार कर रहे हैं, जिससे भारत का शेयर बाजार अभूतपूर्व शिखर पर पहुंच गया है। मैक्वेरी के अनुसार, अकेले खुदरा निवेशकों के पास भारत के इक्विटी बाजार मूल्य का 9% हिस्सा है, जबकि विदेशी निवेशकों के पास 20% से थोड़ा कम है। हालांकि, विश्लेषकों को उम्मीद है कि चुनाव खत्म होने के बाद 2024 की दूसरी छमाही में विदेशी निवेश बढ़ेगा। एक और संभावित चुनौती है। अपनी

अभी भी लगभग पाँच गुना बड़ी है। चीन में कुछ बहुत सारी कंपनियां हैं जो \$100 और \$200 बिलियन से अधिक (मूल्य में) हैं। भारत में उस तरह के पैसे के लिए घर ढूँढ़ना मुश्किल है। लेकिन यह तथ्य कि भारत की जोरदार रैली घरेलू निवेशकों द्वारा संचालित है, देश की ताकत को बढ़ाती है और विदेशी फंड प्रवाह पर इसकी निर्भरता को कम करती है। दूसरी ओर, भारत के पश्चिम और अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ स्वस्थ संबंध

हैं, और वह देश में कारखाने स्थापित करने के लिए बड़ी कंपनियों को आक्रामक रूप से लुभा रहा है। फरवरी में अपने बजट भाषण में, भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने कहा कि 2014 में पहली बार सत्ता में आने के बाद से FDI प्रवाह लगभग 600 बिलियन डॉलर था, जो पिछले दशक के दौरान दोगुना है।

स्नोत-दीक्षा मधोक, सीएनएन द्वारा लेख विश्लेषण से क्यूरेट किया गया।

ECONOMY



इंडन

सुरक्षा को रखिए बरकरार
सुरक्षा होज़ की
तारीख रखिए याद।

एक सपायरी डेट करीब
आने पर अपने
होज़ पाइप बदले.
अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर
से संपर्क करें।

जनहित में जारी

सम्पादकीय

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने साल 2022-23 के लिए जो घरेलू उपभोग व्यव सर्वेक्षण का सारांश जारी किया है, उसका स्वागत किया जा रहा है। लगभग ग्यारह वर्ष के बाद ये आंकड़े जारी किए गए हैं, तो अध्ययन और क्रियान्वयन की दृष्टि से इनका बहुत महत्व है। इधर के वर्षों में आंकड़े न जारी करने के लिए लगातार सरकार की आलोचना हो रही थी। अब इन आलोचनाओं पर विराम लगेगा और विभिन्न अर्थिक व सामाजिक शोध संस्थानों को विचार-मंथन में सुविधा होगी। आंकड़े साफ गवाही दे रहे हैं कि देश विकसित हो रहा है। साल 2011-12 में एक औसत ग्रामीण भारतीय का भोजन खर्च 1,750 रुपये मासिक हुआ करता था, जो साल 2022-23 में बढ़कर 3,773 रुपये हो गया है। इस दौरान शहरी भारतीयों का मासिक भोजन खर्च 2,530 रुपये से बढ़कर 6,459 रुपये हो गया है। गांव हो या शहर, भोजन पर होने वाला खर्च तो दोगुने

भारतीयों के औसत खर्च में गिरावट

से ज्यादा हो गया है, मगर बाकी कुल खर्च में उतनी वृद्धि नहीं हुई है। वैसे भारत में लोगों की आय और खर्च में बहुत असमानता है। अपने देश में अर्थिक रूप से शीर्ष पांच प्रतिशत ग्रामीण और शहरी भारतीय एक महीने में औसतन 10,501 रुपये और 20,824 रुपये खर्च करने लगे हैं। पहले यह आशंका जताई जा रही थी कि भारतीयों के औसत खर्च में गिरावट आई है। जब एनएसएसओ द्वारा तैयार साल 2017-18 के आंकड़े लीक हुए थे, तब इसी आधार पर सरकार की आलोचना हुई थी। बाद में उस पूरी रिपोर्ट को ही सरकार ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया था और उसके बाद से ही यह लग रहा था कि देश में आय के घटने की वजह से प्रशासन आंकड़ों को जारी करने से बचना चाहता है। बहरहाल, रिपोर्ट का सार ही जारी किया

गया है, विस्तृत रिपोर्ट के लिए कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। किसी भी सरकार पर आंकड़े जारी करने का दबाव रहता ही है और सही आंकड़े इसलिए जरूरी हैं, ताकि उनके आधार पर बेहतर विकास योजनाओं का प्रारूप गढ़ा जा सके। यह बात छिपी नहीं है कि बीच में महामारी और लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था में बहुत गिरावट आई थी, तब ऐसे समय के आंकड़ों को जारी न करके नेताओं ने देश को निराशा से ही बचाया, हालांकि अर्थशास्त्री इस दलील को नहीं मानेंगे। जाहिर है, अर्थव्यवस्था के विविध पहलुओं को ज्यादा समय तक छिपाया नहीं जा सकता और कभी न कभी आंकड़े सामने आते ही हैं। बेशक, जारी आंकड़े साफ संकेत कर रहे हैं कि देश विकास की ओर बढ़ रहा है और खर्च के ढर्म में बदलाव आ

रहा है। एक समय था, जब ज्यादातर परिवार अपने लिए भोजन जुटाने में ही खर्च हो जाते थे, पर अब भोजन पर होने वाले खर्च का अनुपात घट रहा है और हम बेहतर जीवन के दूसरे साधनों पर ज्यादा खर्च करने की स्थिति में आ रहे हैं। साल 2011-12 में ग्रामीण और शहरी परिवारों के कुल खर्च में खाद्य उपभोग की हिस्सेदारी क्रमशः 52.9 प्रतिशत और 46.2 प्रतिशत थी। साल 2022-23 में यह घटकर क्रमशः 46.4 प्रतिशत और 39.2 प्रतिशत रह गई है। यह सुखद है कि ग्रामीण भारतीयों को अपनी आय में से आधे से भी कम हिस्सा अब भोजन में लगाना पड़ रहा है। भोजन में भी विविधता आई है और अनाज पर निर्भरता घट रही है। इतना तो तय है कि भारत में खाद्य बाजार का भविष्य उज्ज्वल है। बहरहाल, सरकारी एजेंसियों को भी विस्तृत आंकड़ों का इंतजार रहेगा, ताकि बीते दौरे के साथ तुलना सहजता से संभव हो।

उज्जैन, नागदा, खाचरौद सहित 11 स्टेशनों का होगा पुनर्विकास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधुनिक और तेज रेलवे के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 41 हजार करोड़ की लागत से देश के 554 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प

उज्जैन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधुनिक और तेज रेलवे के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 41 हजार करोड़ की लागत से देश के 554 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प और 1500 रोड ओवर ब्रिज/अंडरपास के शिलान्यास, उद्घाटन व राष्ट्र को समर्पण कार्यक्रम में राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल उज्जैन जिले के नागदा से शामिल हुए। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा नागदा स्टेशन सहित भारतीय रेलवे के 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 1500 आरयूबी, आरओबी, अंडरपास के वीडियो लिंक के माध्यम से शिलान्यास, उद्घाटन समारोह में शामिल होकर बहुत खुश हूँ। देशवासियों की ओर से रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास होने से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को कोटि-कोटि आभार।

रेलवे स्टेशनों के विकास होने से होगा हम सबको गर्व। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नये भारत का नया स्टेशन में बदलने की महत्वाकांक्षा योजना तैयार की थी, जो अमृत भारत स्टेशन योजना अन्तर्गत देश के कई स्टेशनों में विश्वस्तरीय रेल सुविधाओं एवं अत्यधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने का बीड़ा उठाया है। इसी के तहत उज्जैन रेल मण्डल के 11 स्टेशनों को अत्यधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जायेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 41 हजार करोड़ रुपये की लागत से देश के 554 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प और 1500+रोड ओवर ब्रिज, अंडरपास के शिलान्यास व उद्घाटन के अवसर पर नागदा रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल नागदा स्टेशन के पुनर्विकास के वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों के विकास होने से हम सबको गर्व होगा। रेलवे स्टेशनों के अत्यधुनिक विकसित होने पर यह एक ऐतिहासिक कदम है। देश के प्रधानमंत्री ने जो अभूतपूर्व सौगात दी है, जिनका प्रदेशवासियों की

ओर से आभार प्रकट हम सब करते हैं।

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि जिस तरह एयरपोर्ट सुसज्जित एवं अत्यधुनिक हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री ने भी रेलवे स्टेशनों को सुसज्जित बनाने का बीड़ा उठाया है। उसी कड़ी में आज पश्चिम रेलवे के 66 रेलवे स्टेशनों का अमृत रेलवे स्टेशनों के रूप में पुनर्विकास का शिलान्यास किया है। इसमें रतलाम मण्डल के 11 स्टेशन नागदा, खाचरौद, उज्जैन सहित अन्य स्टेशनों का पुनर्विकास किया जायेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास संकल्प की सिद्धि की दिशा में तेजी से बढ़ते कदमों का इस पड़ाव पर पहुँचना, हम सबके लिए गर्व और हर्ष की बात है। मध्यप्रदेश में रेलवे इनफ्रास्ट्रक्चर को उन्नत करने के लिए 77 हजार 800 करोड़ की 32 परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में प्रदेश को रिकॉर्ड 15 हजार करोड़ रुपये का आवंटन और नागदा सहित प्रदेश के 80 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने की योजना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का इन अभूतपूर्व सौगातों के लिए प्रदेश के प्रथम नागरिक होने के नाते, आभार मानते हुए उन्हें दिल से धन्यवाद

देता हूँ। जानकर बहुत खुशी हुई कि नागदा जंक्शन रेलवे स्टेशन में लगभग 26 करोड़ रुपये की राशि से पुनर्विकास के अनेक कार्य किए जाएंगे।

यात्री प्रतीक्षालय का पुनर्निर्माण, नए बुकिंग-आरक्षण कार्यालय, फर्नीचर, बैन्चेस, संकेतक लागेंगे, यात्रियों के सुगम आवागमन हेतु 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज और दिव्यांगजन के लिए रैम्प बनेगा। स्टेशन के लिए अलग से नए प्रवेश-निकास द्वारा बनेंगे, परिसर का सौन्दर्य एवं समतलीकरण होगा और प्रकाश व्यवस्था के सुधार के कार्य किये जाएंगे। जिस आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैचारिक बदलाव की देश में आवश्यकता थी, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में समय का वह दौर अब शुरू हो गया है। सरकार के एक के बाद एक ऐतिहासिक निर्णयों ने बड़े-बड़े बदलाव कर, देश की विकास यात्रा को नई गति और दिशा दी है। देश में पहली बार विकसित भारत संकल्प यात्रा की अभिनव पहल से वंचित वर्गों, पिछड़े और दूरस्थ अंचलों के निवासियों को विकास की गारंटी मिली है। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि सरकार हर भारतीय परिवार के कल्याण और संतुष्टि के लिए कार्य कर रही है, यही कारण है

कि आज सामान्य देशवासियों की सवारी भारतीय रेल दुनिया का श्रेष्ठ रेल नेटवर्क है। रेलवे स्टेशन जिस शहर में होता है, वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण लैंड मार्क होता है यह एक तरह से नगर का झारोखा होता है। स्टेशन जितना अच्छा और सुविधाओं से भरा होगा, उस शहर के प्रति भी लोगों में भावना भी वैसी ही विकसित होगी। इसलिए जरूरी है कि स्टेशन के पुनर्विकास के कार्यों की गुणवत्ता, सौदर्योंकरण और स्वच्छता के कार्य एवं प्रबंधन विश्व स्तरीय हो। स्टेशन नागदा के नागरिकों के कर्तव्य पालन का आदर्श बनेगा। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कार्यक्रम में रेलवे द्वारा छात्रों की विविध प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में नार पालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गेहलोत, कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा, शहर के गणमान्य नागरिक, छात्र-छात्राएं, मीडिया के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्री हितेंद्र दीक्षित ने किया। इस अवसर पर देशभक्ति गीत श्री वीए सिसौदिया व श्रीमती सिसौदिया ने प्रस्तुत किया।





शार्क टैंक भूल जाओ

स्टार्टअप कहानी आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क को जानिये

Accelerated Incubator

Assistive Technology

Fintech for Inclusion

Making of Rancho

Towards 100% RE

R&D to Scaled Commercialisation

शार्क टैंक को भूल जाइए, असली स्टार्टअप कहानी आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क में आईआईटी मद्रास इनक्यूबेशन सेल में सामने आ रही है, स्टार्टअप के साथ इसकी सफलता दर 80% है!

- 332 संपन्न स्टार्टअप को विकसित करने में सफलता।
- सामूहिक रूप से इसका मूल्य प्रभावशाली \$ 4.6 बिलियन है।
- 1.1 अरब डॉलर का पर्याप्त निवेश आकर्षित किया।
- यूनिफोर ने यूनिकॉर्न का प्रतिष्ठित दर्जा हासिल कर लिया है।

इतिहास

IITMIC ने 400 करोड़ रुपये की शुरुआती पूँजी के साथ शुरुआत की और अब तक उन्होंने व्याज सहित 600 करोड़ रुपये लौटाए हैं।

IITMIC ने कोई अनुदान नहीं लिया क्योंकि वे एक टिकाऊ BOOTSTRAPPED व्यवसाय बनाने के बारे में स्टार्टअप्स को अनुभव और प्रदर्शन करना चाहते थे।

2023 के अंत तक, IITMIC के पास 45,000 करोड़ रुपये (\$5.4 बिलियन) मूल्य के 351 Deep Tech Start up portfolio है। IITMIC से 8000-9000 प्रत्यक्ष नौकरियां भी पैदा हुई हैं।

प्रमुख सफलता की कहानियाँ

- Ather Energy : स्टार्टअप में एथर एनर्जी (750-800 मिलियन डॉलर मूल्यांकन, इसलिए यूनिकॉर्न का दर्जा आसन्न है)। उन्होंने आईआईटीएमआईसी में चेसिस से लेकर मोटर तक सब कुछ बनाया।

- Medi buddy - अब तक 200 मिलियन डॉलर जुटा चुका है और वर्तमान में इसका मूल्य 500 मिलियन डॉलर के करीब है। उनके इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स ने 9500

करोड़ रुपये का फंड जुटाया है और 1,300 पेटेंट तैयार किए हैं।

IITMIC पर मजेदार तथ्य

- उनके स्टार्टअप की Survival Rate दर सामान्यतः 80% Vs Normal Start up Survival Rate 4-6% है।
- IITMIC योजना 2024 को 366 पेटेंट और 100 स्टार्टअप लॉन्च के साथ समाप्त करने की है।
- इनमें से कई कंपनियों में उनकी 1% इक्सिट भी है। वे सालाना 50-60 करोड़ रुपये कमा रहे हैं।

108x योजना!

● 2030 तक एक विजन योजना-इनक्यूबेटस की संख्या प्रति वर्ष 1,000 तक बढ़ाना, जो आज लगभग 45 है-उनका लक्ष्य टियर-2, टियर-3 और टियर-4 संस्थानों में 50 से 100 इनक्यूबेटरों के साथ साझेदारी करना और अपने इनक्यूबेटस का पोषण करना है।

The Circle of Five

भारतीय अनुसंधान एवं विकास से उत्पन्न 50 उत्पादों का पोषण करें ताकि प्रत्येक 1,000 करोड़ का वार्षिक राजस्व अर्जित कर सकें किसी भी क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकीविदों को शीर्ष 2% में लाने के लिए-यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम करें कि भारत को पांच क्षेत्रों में शीर्ष पांच देशों में पहचाना जाए।

- आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क, एक विशाल, 11.5 एकड़, 1.2 मिलियन वर्ग फुट का परिसर जो कॉर्पोरेट आर एंड डी कार्य के लिए प्लग-एंड-प्ले सुविधाएं प्रदान करता है।

- विनिर्माण, रोबोटिक्स, ऑटोमेटिव (ईवी), सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू किए गए हैं (एआई, एमएल, मेटावर्स, उत्पाद आधारित, जेनरेटिव एआई), स्वास्थ्य

तकनीक, चिकित्सा उपकरण, ऊर्जा क्षेत्र।

● 450 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित-लगभग 40 कंपनियों की मेजबानी-अगले 5 वर्षों में 150 कंपनियां।-550 आईआईटीएम संकाय सदस्यों में से 25% अनुसंधान पार्क में शामिल हैं।

निष्कर्ष

आईआईटीएमआईसी में सभी स्टार्टअप, जो प्रमुख समस्याओं को सुलझाने पर केंद्रित हैं, उनका पोषण

केवल आईआईटी मद्रास के पारिस्थितिकी तंत्र के कारण ही संभव हो सका है।

10 साल पूरे होने पर, सीईओ याद करते हैं कि कैसे आईआईटीएम इनक्यूबेशन सेल सरकार से किसी अनुदान या समर्थन के बिना शुरू हुआ था।

शुरुआत का उद्देश्य आने वाले उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने में समर्थन और मदद करने के लिए एक माध्यम बनना था और इसके साथ ही

उनके साथ यात्रा का अनुभव करना था।

अब तक छोटे कदमों से शुरू की गई यात्रा अब मूल्य और प्रभाव दोनों ही दृष्टि से बड़ी हो रही है।

Source : IITMIC website, NDTV के साथ CEO का साक्षात्कार, New Paper articles, अशोक झुनझुनवाला (अध्यक्ष, आईआईटीएम रिसर्च पार्क) interviews.



A LOOK AT IIT MADRAS RESEARCH PARK

The research park was established in 2008, as part of IIT Madras efforts to concentrate on transnational research

Spread across
11.42 acres

Provides
1.2 million sq ft
of workspace

16 departments

600 faculty

3,500 research scholars

भ्रष्टाचार करने के लिए नोबेल पुरस्कार मांग रहे हैं केजरीवाल : पूनावाला

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि यह कैसी विडम्बना है कि भ्रष्टाचार के सरगना केजरीवाल दिल्ली की जनता से घोटाला तथा भ्रष्टाचार करने के लिए माफी मांगने की बजाय अपने लिए नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहे हैं।

श्री पूनावाला ने पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि श्री केजरीवाल, सत्येन्द्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सहित आम आदमी पार्टी (आप) के तमाम नेताओं के भ्रष्टाचार की सच्चाई उजागर हो गयी है। उन्होंने आप पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि भ्रष्टाचार के सरगना केजरीवाल दिल्ली की जनता के साथ घोटाला और भ्रष्टाचार करने के लिए माफी मांगने की बजाय अपने लिए नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि एक वर्ष पहले जब सिसोदिया न्यायालय के आदेश

अनुसार सलाखों के पीछे गए थे, तब श्री केजरीवाल उनके काले कारनामों के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे थे। सिसोदिया एक साल से जेल के सलाखों के पीछे हैं और देश के किसी न्यायालय ने उनको राहत नहीं दी है। न्यायालय ने शराब घोटाले में 368 करोड़ रुपये के हेराफेरी की बात कही है। उन्होंने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि आज देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान गाने के बोल बदल चुके हैं। आज इस गाने के बोल हो गए हैं-दिल्ली वासियों के मुख्यमंत्री की हालत क्या हो गई जनता रूपी भगवान, कितना बदल गया ये इंसान। ये वही केजरीवाल है जो आम आदमी की पार्टी की शुरुआत होने से पहले अन्ना हजारे की छत्रछाया में कहा करता था कि घोटाले का आरोप लगाने मात्र पर ही पहले आरोपी नेता का इस्तीफा होगा और उसके बाद जांच होगी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल बच्चों की कसम खाकर कहा करते थे कि आम आप कभी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करेगी और श्री लालू प्रसाद यादव, श्रीमती सोनिया गांधी की पार्टी के बाद तीसरा नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। इसके बाद उन्हें भ्रष्टाचार करने के लिए भाजपा द्वारा बोलते हुए हुए कहा कि श्री केजरीवाल को भ्रष्टाचार करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। इन लोगों ने दवा से दारू तक, मोहल्ला क्लीनिक से शराब के टेके तक, टैक्स से कक्षा तक, बस से शीशमहल तक हर विभाग को ठगा और लूटा है। हर विभाग को श्री केजरीवाल ने अपनी काली कमाई और रिश्तखोरी का स्रोत बनाया है।





दुनिया भर के पाठक Google GeminiOS damage control post पढ़ रहे हैं और पढ़कर आश्वस्त कित हैं।

प्रौद्योगिकी जगत में और विशेषज्ञों द्वारा यह अनुमान लगाया जा रहा है कि, गूगल सच नहीं बता रहा है। उनका उत्पाद केवल टेक्स्ट उत्पाद है जिसमें कुछ गंभीर मुद्दे हैं।

यदि आप थोड़ा भी जानते हैं कि ये मॉडल कैसे बनाए जाते हैं, तो आप जानते हैं कि आपको ये गलत उत्तर one-off innocent mistakes के माध्यम से नहीं मिलते हैं।

जेमिनी के labelling efforts, training, fine-tuning, prompt design, QA/verification कई वर्षों को दर्शाते हैं- यह सब उस टीम द्वारा निर्देशित है जिसने इसे बनाया है।

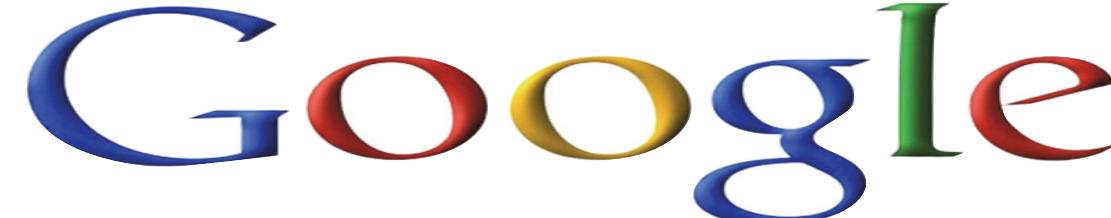
आप यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि इसे जारी करने से पहले, कई लोगों ने उत्पाद को आंतरिक रूप से आजमाया है, वरिष्ठ PMs and VPs को कई डेमो दिए गए थे, कि उन सभी को लगा कि यह ठीक है, और अंततः उन सभी ने रिलीज पर हस्ताक्षर कर दिए।

Gemini की विफलता के साथ, क्या Google अभी भी User Friendly कंपनी है?

विशेषज्ञों के अनुसार, जेमिनी एक ऐसा उत्पाद है जो बिल्कुल डिजाइन के अनुसार काम करता है,

उस विचारधारा का कुछ हिस्सा दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के बारे में आपकी या मेरी सोच के साथ align

किया है; मदद करने के बजाय, उनका परिणाम आम तौर पर दशकों की असफलताओं (और लाखों पीड़ितों)



और इसे बनाने वाले लोगों के मूल्यों का सटीक प्रतिबिंब है।

ऐसा प्रतीत होता है कि उपयोगकर्ता को तथ्य देने से पहले विचारधारा को प्राथमिकता देने के लिए अपने AI को प्रशिक्षित करना न केवल स्वीकार्य है बल्कि वांछनीय भी है। इतिहास को संशोधित करना, वर्तमान को अस्पष्ट करना, और ऐसी जानकारी को पूरी तरह छिपाना जो कंपनी (कर्मचारियों) की अच्छी धारणा से मेल नहीं खाती।

मारियो ज्यूरिक के अनुसार

मुझे इसकी परवाह नहीं है कि

हो भी सकता है और नहीं भी। मानव इतिहास के बारे में थोड़ी भी जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह कितना अविश्वसनीय रूप से गैर-जिम्मेदाराना है। एक ऐसी प्रणाली का निर्माण करें जिसका लक्ष्य मानव ज्ञान का एक आधिकारिक संग्रह बनना है (Google के मिशन वक्तव्य को याद रखें?), लेकिन जो वास्तव में तथ्यों पर विचारधारा को प्राथमिकता देता है। इतिहास ऐसे कई लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने अधिक अच्छे के लिए इस प्रकार के नैतिक लचीलेपन का प्रयास

के रूप में सामने आया।

विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसा उत्पाद बनाना मूर्खता से परे है जो स्पष्ट रूप से आपकी कंपनी के सामाजिक एजेंडे को ग्राहक की जरूरतों से पहले रखेगा।

इसके बारे में सोचें-Google की खोज-इसके सभी मुद्दों के लिए-एक अच्छा उपकरण माना गया है, क्योंकि यह सटीक और उपयोगी जानकारी प्रदान करने पर केंद्रित है। इसका मिशन उपयोगकर्ताओं के लक्ष्यों के साथ सरेखित था (मुझे जिस सामान की जरूरत है उसके लिए सही उत्तर

तक पहुंचाएं, और तेजी से!)। इसीलिए हम सभी इसका उपयोग करते हैं। लेकिन उन्होंने इसका उल्टा किया है। जेमिनी के बाद, उपयोगकर्ता-केंद्रित कंपनी के बजाय, तश्शहद्यद्वारा को पहले एक सक्रिय संगठन के रूप में माना जाएगा-जो अपने (कर्मचारियों के) सामाजिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उपयोगकर्ता से झूठ बोलने के लिए तैयार है।

कुकीज, विज्ञापन, गोपनीयता संबंधी मुद्दे या YouTube सामग्री मॉडरेशन को भूल जाइए Google ने

50% से अधिक आबादी को इस परिदृश्य से गुजरने और मुख्य व्यवसाय और इसे चलाने वाले लोगों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए मजबूर किया है।

जेमिनी निर्माण के साथ समस्या यह बताती है कि कैसे Google के Algorithm के परिणामस्वरूप nintended biased हो सकते हैं जैसे कि बड़े ब्रांड वेबसाइटों का पक्ष लेने वाला bias जो Google के समीक्षा प्रणाली alogirithm में खोजा गया था।



मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी शिकायत की, वायरल पोस्ट में पीएम मोदी, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की पर एक सवाल के लिए एआई मॉडल के पूर्वग्रह को दिखाने का दावा किया गया है।

दावा किया गया कि जब फासीवाद के बारे में सवाल पूछा गया तो जेमिनी एआई टूल ने पीएम मोदी के बारे में उचित जवाब दिखाया। हालांकि, जब डोनाल्ड ट्रम्प और जेलेंस्की के बारे में यही सवाल पूछा गया, तो एआई टूल ने स्पष्ट जवाब देने से इनकार कर दिया।

इससे पहले दिन में, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक्स यूजर की शिकायत पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि प्लेटफॉर्म आईटी नियमों और अन्य कानूनों का उल्लंघन करता है। चंद्रशेखर ने तश्शहद्यद्वारा और Meity को टैग करते हुए मामले में आगे की कार्रवाई का संकेत देते हुए कहा ये आईटी अधिनियम के मध्यस्थ नियमों (आईटी नियमों) के नियम 3(1)(बी) का सीधा उल्लंघन है और आपाधिक संहिता के कई प्रावधानों का उल्लेखनीय है।

पीएम मोदी के खिलाफ कथित तौर पर पक्षपातपूर्ण होने के कारण जेमिनी आलोचना के घेरे में आ गया, जब एक एक्स यूजर ने सोशल

नौकरी से निकाले जाएंगे या देंगे इस्तीफा सुंदर पिंपाई

Gemini AI की असफलता के बाद, Sundar Pichai विवादों में हैं। हेलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा का मानना है कि जेमिनी की विफलता के कारण, गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को बर्खास्त कर देना चाहिए या उन्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए।

लीड होने के बावजूद विफल

हुआ गूगल

दरअसल, जब सोशल मीडिया साइट एक्स (पहले टिक्टॉक) पर एक यूजर ने लिखा सर जी, गूगल जेमिनी देखा? यह श्वेत लोगों के अस्तित्व को

मानने से इंकार कर रहा है। सुंदर पिचाई भाग्यशाली हैं, उनका रंग गोरा नहीं है। इसका जवाब देते हुए अरोड़ा ने लिखा-मेरा अनुमान है कि उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए या उन्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि एआई पर लीड होने के बाद वह इसमें पूरी तरह से विफल हो गए हैं और दूसरों को इस पर कब्जा करने दिया है।

क्या है Gemini AI?

गूगल ने हाल ही में वैश्विक स्तर पर यूजर्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करते हुए अपने चैटबॉट

बार्ड को जेमिनी के रूप में रोबिंट किया है। गूगल के अनुसार, यूजर अब 230 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 40 से अधिक भाषाओं में जेमिनी प्रो 1.0 मॉडल के साथ जुड़ सकते हैं।

जेमिनी एडवांस्ट गूगल One AI प्रीमियम प्लान का हिस्सा है, जिसकी कीमत 19.99/माह है, जो दो महीने के फ्री ट्रायल के साथ शुरू होती है। गूगल ने लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट में बताया गया है, एआई प्रीमियम ग्राहक अलग-अलग गूगल एप्लिकेशन जैसे जीमेल, डॉक्स, स्लाइड्स, शीट्स और अधिक (जिसे पहले ड्रूएट एआई के रूप में जाना जाता था) में जेमिनी के इंटीग्रेशन का अनुमान लगा सकते हैं।

यहां से शुरू हुआ विवाद

लॉन्च के एक हफ्ते के अंदर ही यह विवादों में आ गया। एपी रिपोर्ट के अनुसार, गूगल ने 23 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा जिले में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के काफिले को निशाना बनाकर जैश-ए-मोहम्मद द्वारा किए गए कायरतापूर्ण आतंकी हमले के जवाब में था। हमले में कम से कम 40 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने मजबूत इरादे और धैर्य के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि जब भारत को कोविड के बीच चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चुनौती दी गई तो त्वरित और प्रभावी जवाब ही इससे निपटने का उचित उपाय था।

विवादों में आने के बाद, गूगल ने कहा कि उसने चैटबॉट के इमेज जनरेटर को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया है। गूगल के सच इंजन और अन्य व्यवसायों की देखरेख करने वाले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, प्रभाकर राघवन ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, यह स्पष्ट है कि यह फीचर लक्ष्य से

1000 वीडियो रथ, 6000 बॉक्स चुनाव से पहले ही 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का भाजपा ने शुरू किया महा-अभियान

एक पखवाड़े तक चलने वाले इस महा-अभियान के तहत बीजेपी देशभर में कुल 1000 वीडियो रथ कुल 4000 विधानसभा क्षेत्रों में दौड़ाएगी। इसके अलावा देशभर में करीब 6000 जगहों पर सुझाव पेटिका भी रखेगी, ताकि लोग उसमें अपने-अपने सुझाव डाल सकें। पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस दौरान डेर-टू-डेर कैम्पेन भी चलाएंगे। पार्टी महासचिव सुनील बंसल, तरुण चुध और संयुक्त महासचिव (संगठन) शिव प्रकाश ने इस महा-अभियान की सफलता के लिए सोमवार को अलग-अलग राज्यों से आए 82 पार्टी नेताओं के साथ एक कार्यशाला में चर्चा की।

यह अभियान 15 मार्च को समाप्त होगा। इसका लक्ष्य बीजेपी के घोषणा पत्र (संकल्प पत्र) के लिए एक करोड़ लोगों का सुझाव मांगना है।

बीजेपी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नह्ने अभियान की शुरूआत करते हुए कहा,

जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे-वैसे सभी राजनीतिक दलों की ओर से चुनावी जीत की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में केंद्र की सत्ताखड़ भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र के लिए देशभर के करीब एक करोड़ लोगों से सुझाव मांगने का महा अभियान शुरू किया है। पार्टी अध्यक्ष जे पी नह्ने सोमवार को पार्टी के इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरूआत की और 'विकसित भारत-मोदी की गारंटी' स्लोगन वाले 25 वीडियो रथों को हरी झंडी दिखाकर रखाना किया।

'देश के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में वीडियो वैन के माध्यम से हम लगभग 250 स्थानों पर समाज के विभिन्न वर्गों के साथ संवाद करेंगे और उनके सुझावों का भी हम अपने घोषणापत्र में समावेश करेंगे।' उन्होंने कहा कि इसके साथ ही पार्टी की ओर से एक विशेष 'मिस्टर कॉल' नंबर जारी किया जाएगा और इसके जरिए भी लोगों से सुझाव मंगवाए जाएंगे।

वीडियो वैन को 'विकसित भारत-मोदी की गारंटी' रथ का नाम दिया गया है। इसमें भारत को एक विकसित देश बनाने के प्रधानमंत्री



नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया है। नह्ने ने कहा, 'ये वीडियो वैन सारे देश में जाएंगी और लगभग एक करोड़ से ज्यादा सुझाव पत्र हमारे पास 15 मार्च तक पहुंचेंगे और उनका समावेश करके हमारा संकल्प पत्र बनेगा, जो 2024 में विकास के लिए एक लंबी छलांग

लगाने के लिए होगा।'

उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र के लिए सुझाव मांगने का कार्य 15 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी का घोषणापत्र तैयार करने का काम प्रगति पर है। उन्होंने एक फोन

नंबर जारी किया और लोगों से इस पर मिस्टर कॉल देने और पार्टी के घोषणापत्र के लिए अपने सुझाव देने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग नमो ऐप पर भी अपने सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी सार्वजनिक इनपुट संकल्प पत्र में योगदान देंगे, जो विकसित राष्ट्र के लिए पार्टी के दृष्टिकोण को आकार देंगे।

नह्ने कहा कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्वमित्र भारत की आकांक्षाएं, जो 2014 में अकल्पनीय लगती थीं, अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वास्तविकता बन रही हैं।

उन्होंने कहा कि भारत अमृत काल के दौरान विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए तैयार है।

भाजपा ने लगातार तीसरी बार मोदी के नेतृत्व में सत्ता बरकरार रखने का विश्वास जताया है और 543 सदस्यीय लोकसभा के लिए 370 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया है।

राज्यसभा चुनाव अखिलेश यादव के लिए नई चुनौती लेकर आया है, क्रॉस वोटिंग का डर

लखनऊ। अखिलेश यादव के लिए राज्यसभा चुनाव एक नई चुनौती लेकर आया है। 10 सीटों के चुनाव में भाजपा ने 8 कैंडिडेट उतार दिए हैं। विधायकों की संख्या के आधार पर देखें तो 7 सीटों पर भाजपा और 3 पर सपा आसानी से जीतने की स्थिति में हैं, लेकिन भाजपा ने 8वें उम्मीदवार के तौर पर

संजय सेठ का नामांकन कराके खेल कर दिया। ऐसे में अब सपा को आशंका है कि उसके ही कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में भाजपा को 8 सीटें मिल सकती हैं। कभी सपा में ही रहे संजय सेठ नामी बिल्डर और कारोबारी हैं। माना जा रहा है कि उनके ही प्रभाव का इस्तेमाल करके

भाजपा सपा को नुकसान पहुंचा सकती है।

यह डर तब और बढ़ गया, जब सोमवार शाम को अखिलेश यादव के डिनर में 8 विधायक नहीं पहुंचे। इन विधायकों में अखिलेश यादव के करीबी कहे जाने वाले मनोज पांडेय भी हैं, जो सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। इसके अलावा जलालपुर के विधायक राकेश

पल्लवी पटेल भी डिनर पर नहीं गई। अमेठी के महाराज प्रजापति, चैल की विधायक पूजा ने भी दूरी बना ली। इन विधायकों को लेकर सपा को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। सपा के

एक विधायक जाहिद बेग ने भी माना कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। उन्होंने तो गुस्से में यहां तक कहा कि

बिकाऊ लोगों को जनता माफ नहीं करेगी। जाहिद बेग ने

लोग नहीं आए। शायद वे अपने काम में बिजी थे। बिकाऊ लोगों को जनता माफ नहीं करेगी। यदि उन्होंने पैसे लिए होंगे तो जनता उन्हें जूतों से मारेगी। खुद अखिलेश यादव ने भी सोमवार को कहा था कि भाजपा दबाव डालती है, धमकाती है और

एजेंसियों का डर दिखाती है। लेकिन इस चुनाव में यह सब काम नहीं करेगा। बता दें कि सपा के तीन उम्मीदवारों में से एक जया बच्चन हैं तो दूसरे नौकरशाह रहे अलोक रंजन हैं। इसके अलावा दलित नेता गमजी लाल सुमन को मौका मिला है।

दरअसल भाजपा ने जयंत चौधरी को पहले ही अपने पाले में शामिल कर लिया है। इसके अलावा राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के भी दो विधायक हैं और उधर से भी संकेत मिले हैं कि भाजपा का ही समर्थन करेंगे।

ऐसे में सपा के लिए बाहर से भी स्थिति कमज़ोर है और अब पार्टी में ही क्रॉस वोटिंग का डर उसके लिए एक उम्मीदवार की हार के नतीजे के तौर पर सामने आ सकता है। इस बीच खबर है कि सपा के तीन बागी विधायक राकेश पांडेय, राकेश प्रताप सिंह और अभ्य सिंह एक ही गाड़ी से निकले हैं। इन लोगों ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की बात कही है।

कांग्रेस को एक और बड़ा झटका पूर्व केंद्रीय मंत्री नारण राठवा ने छोड़ी पार्टी, बेटे संग भाजपा में जाएंगे

गुजरात। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और तगड़ा झटका लगा है। अब गुजरात के दिग्गज कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारण राठवा ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है और भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं। वहीं उनके बेटे संग्राम राठवा भी भाजपा में जाएंगे।

जीतकर लोकसभा पहुंचे। इसके अलावा 2004 से 2009 तक रेल राज्य मंत्री रहे। हालांकि 2009 में उन्हें भाजपा प्रत्याशी रामसिंह राठवा के सामने हार का सामना करना पड़ा था।



गुजरात में अभी कांग्रेस को और भी झटके लग सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि अहमद पटेल भी कांग्रेस नेतृत्व से नाराज है। दरअसल दिल्ली के बदले आम आदमी पार्टी ने अन्य राज्यों में कांग्रेस के साथ सीट बट्टवारे पर सहमति बनाई है। ऐसे में चर्चा है कि भरुच सीट आम आदमी पार्टी को दी जा सकती है। वहीं अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल या फिर उनके भाई फैसल को यहां से टिकट पाने की उम्मीद थी। ऐसे में चर्चा है कि अहमद पटेल भी कांग्रेस से नाराज हैं।



राजनीतिक इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम तुष्टिकरण की जननी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आजादी के बाद नेहरू से वर्तमान तक पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति को समर्पित रही है। आजादी के बाद घरेलू ही नहीं, विदेशी नीति भी तुष्टिकरण से तय होती थी। सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि जिन मुसलमानों के नाम पर कांग्रेस ने देश में तुष्टिकरण की नीति का आगाज किया उन मुसलमानों की माली हालत सुधरने की बजाय बिगड़ती चली गई। दूसरी विडंबना यह हुई कि कांग्रेसी तुष्टिकरण का संक्रमण क्षेत्रीय पार्टियों, मीडिया, बुद्धिजीवियों तक होता गया।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण के बलबूते ही सत्ता में आई थी। सत्ता पर काबिज होने के बाद से तृणमूल की सरकार ने मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए हिन्दुओं व दूसरे समुदायों की पूरी तरह अनदेखी की। हिन्दुओं के धर्मिक उत्सवों और यात्राओं तक में सरकार ने अड़चन लगाने का काम किया। पश्चिम बंगाल में हिन्दुओं की जो दुर्दशा हो रही है, वो किसी छिपी नहीं है। तृणमूल के नेता और कार्यकर्ता जिस तरह का अत्याचार कर रहे हैं, वो सुनकर हैरानी होती है कि हम किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और पश्चिम बंगाल में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी दुई सरकार है। पश्चिम बंगाल हो या फिर दिल्ली, मुस्लिम तुष्टिकरण को लेकर इनमें होड़ है। दिल्ली के दंगों में आम आदमी पार्टी के नेताओं की भूमिका सर्वविदित है। दिल्ली में शाहीन बाग प्रदर्शन के पीछे भी मुस्लिम तुष्टिकरण वाली राजनीतिक ताकतें अपना चेहरा चाहकर भी छुपा नहीं पाई थीं। तेलंगाना में जब बीआरएस और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तब वहां मुस्लिम

तुष्टिकरण की राजनीति कर रही ममता बेनर्जी

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24-परगना जिले में कालिंदी नदी के किनारे बसा गांव संदेशखाली पिछले कई दिनों से चर्चाओं में है। तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख और उसके दो सहयोगियों पर यहां की महिलाओं ने कथित अत्याचार और यौन उत्पीड़न के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। संदेशखाली की पीड़िताओं ने जो बातें जिम्मेदार लोगों को बताई हैं, वह 21 वीं सदी में अकल्पनीय है। ऐसे में अहम सवाल है कि कोई शाहजहां शेख कैसे इतना निरंकुश हो जाता है? शाहजहां जैसे अत्याचारियों को ताकत कहां से मिलती है? इन सवालों का जवाब भाजपा प्रवक्ता एवं सांसद सुधांशु त्रिवेदी के बयान के छिपा है। सुधांशु के अनुसार, 'जो कुछ संदेशखाली में हो रहा है वो मात्र एक घटना नहीं बल्कि एक राजनीति सोच है, जो 78 वर्ष पूर्व नोआखाली से लेकर आज के संदेशखाली तक बंगाल के लिए नासूर बनती जा रही है। शाहजहां शेख एक व्यक्ति नहीं एक प्रवृत्ति है जिसे मात्र बंगाल में नहीं बल्कि पूरे भारत में एक विशेष प्रकार का सेक्युलर संरक्षण प्राप्त है।'

तुष्टिकरण ही राज्यनीति था। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल जब सरकार की हिस्सेदारी थी, तब वहां भी मुस्लिम तुष्टिकरण चरम पर था।

आजादी के बाद देश में जिस मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति को जो बीज बोया गया, वह आगे चलकर बटवृक्ष बन गया। भारत दुनिया का इकलौता देश बना जहां बहुसंख्यकों के हितों की कीमत पर अल्पसंख्यकों को बरीयता दी गई। कांग्रेसी तुष्टिकरण का पहला नमूना आजादी के तुरंत बाद देखने को मिला जब देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने गुलामी के पहले कलंक को मिटाने के लिए भव्य सोमनाथ मंदिर बनाने की पहल की। लेकिन मुस्लिम परस्ती के चलते प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने न सिर्फ सोमनाथ मंदिर के नवीनीकरण और पुनर्स्थापना के कार्य से खुद को अलग कर लिया बल्कि तत्कालीन सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आदेश दिया कि मंदिर निर्माण में सरकार का एक भी पैसा नहीं लगना चाहिए। इतना ही नहीं, जब राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने जाने लगे तब नेहरू ने उन्हें रोकने की नाकाम कोशिश भी की।

वास्तव में, अल्पसंख्यकवाद और मुस्लिम तुष्टिकरण ही भारत के छद्म

धर्म (पंथ) निरपेक्षतावाद की मूल धर्मी है। इस देश के मुसलमानों का खुश रहना नहीं, उन्हें खुश रखने के लिए हरसंभव प्रयत्न का नाम है सेक्युलरिटी। जैसे गरीबी हटाने का नारा जीवित रखने के लिए गरीब बनाकर रखना एक राजनीतिक आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार से इस देश के मुसलमानों को अपनी पूजा पद्धति रोजा-नमाज और मस्जिद सहित यहां की मुख्य सांस्कृतिक और राष्ट्रीय धारा न बनने देकर उसके समानांतर एक मुस्लिम मजहबी धारा बनाकर रखना भी वोट राजनीति की जरूरत है।

वोट राजनीति की इस विवरशता को कतिपय राजनीतिक दल, दल विहीन राजनेता और बुद्धिवादी देश का स्थायी भाव बना देने की जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। स्वभावतरू पंथनिरपेक्ष भर को सुनियोजित ढंग से पंथ और मजहब के संदर्भ में सोचने, जीने और अपना मानस बनाने को कहा जा रहा है कि यदि ऐसा सोचा और किया न गया तो देश साम्प्रदायिकता की आग में जलकर राख बन जायेगा। यदि संक्षेप में और कुछ वाक्यों में कहें तो आज के भारत की धर्म (पंथ) निरपेक्षता मुस्लिम सापेक्षता का पर्याय है। दोनों एक दूसरे के दास हैं। दोनों की आधार धर्म है

सत्ता राजनीति। यह मान लिया गया है कि मुस्लिम सापेक्ष न होना पंथनिरपेक्षता का विरोधी होना है। यह कि यदि हमारी सोच का केंद्र बिंदु मुसलमान नहीं हैं तो हम भारत राष्ट्र को तोड़ने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और यह कि यदि हम अपने आचार विचार से हिन्दू विरोधी नहीं हैं तो हम सेकुलर नहीं हैं। अतएव यदि हमें सेकुलर बने रहना है तो हमें चाहिए कि हम कश्मीर घाटी से भगा दिये गये हिन्दुओं की पीड़ि प्रताड़ना, उनके दुख और दैन्य की बात न करें। कहैयालाल की हत्या और संदेशखाली पर मुंह बंद रखें। यानी हिन्दुओं पर होने वाले अत्याचारों जिसमें सरकारें और राजनीति दल शामिल हैं, उन्हें अनदेखा करें।

कांग्रेस की इस तुष्टिकरण की नीति का असर दूसरी राजनीतिक पार्टियों पर भी पड़ा और वे मुस्लिम वोट बैंक छिटकने के डर से हिन्दुओं के हित में बोलने से कत्री काटने लगीं। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, एन चंद्रबाबू नायडू, अरविंद केजरीवाल, चंद्रशेखर राव जैसे नेताओं की मुस्लिमपरस्ती एक दिन में नहीं आई है। यह सब कांग्रेसी तुष्टिकरण रूपी वटवृक्ष के फल हैं। दरअसल कांग्रेस द्वारा क्षेत्रीय

अस्मिताओं की उपेक्षा और तानाशाही से उपजी क्षेत्रीय पार्टियों ने मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए मुसलमानों के सशक्तिकरण की बजाय तुष्टिकरण का कांग्रेसी फार्मूला अपना लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि एक ओर मुसलमानों का पिछड़ापन बढ़ा तो दूसरी ओर कट्टरपंथ को उर्वर जमीन मिली। 'तुष्टिकरण' की राजनीति ने मुख्य रूप से मुस्लिमों के बीच की 'मलाईदार परत' को ही फायदा पहुंचाया। इससे कथित धर्मनिरपेक्ष राजनीति का खोखलापन उजागर होता है। कांग्रेस का इतिहास खुद इस बात का गवाह है कि उसने अपनी पूरी राजनीति तुष्टिकरण को आधार बनाकर ही की है अल्पसंख्यकों में भी उसने सबसे अधिक मुस्लिम वोटों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि मुस्लिम वोट देश के कई हिस्सों में निर्णायक सांखित होते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के बजट पर पहला हक मुसलमानों का बनता है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत की बड़ी वजह मुसलमानों का थोक वोट मिलना था। पिछले साल मुस्लिम वोटों की बदौलत कांग्रेस तेलंगाना में सत्ता हासिल करने में सफल रही।

राजनीतिक दल वोट बैंक के लिए तुष्टिकरण का सहारा लेते आए हैं। राजनीतिक दलों ने अपने एजेंडे के हिसाब से धर्म व संप्रदाय बाट रखे हैं और उसके तुष्टिकरण में वो किसी भी हृदय तक चले जाते हैं। सच्चाई यह है कि तुष्टिकरण देश के विकास, सद्व्यवहार, भाईचारे, सुरक्षा और शांति के लिए हानिकारक है। मौकापरस्त, स्वार्थी और गलत प्रवृत्ति के व्यक्ति तुष्टिकरण की आड़ में पाशविकता करते हैं जो शाहजहां शेख और उसके गुर्गे ने संदेशखाली में किया।

लव जिहाद धरने पर बैठी महिलाएं



छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में दो अलग-अलग मामलों में लापता बेटियों की तलाश के लिए माँओं ने सीएम डॉ. मोहन यादव से गुहार लगाई है। इस दौरान दोनों माँ हाथों में पोस्टर लिख शहर के शहीद स्मारक पर धरना देने बैठ गईं। दोनों महिलाओं ने मुस्लिम लड़कों पर बेटियों को भगा ले जाने के साथ ही लव जिहाद का आरोप लगाया है। लापता लड़कियों का मामला 17 जनवरी और 29 जनवरी का बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को समझाने का प्रयास किया। इसके साथ ही आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही लड़कियों को ढूँढ लिया जायेगा। समझाने के बाद दोनों महिलाएं धरने से उठीं।

छिंदवाड़ा के कोतवाली थाना में यह मामला आज सामने आया। जब कई दिनों से लापता दो हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों द्वारा भगा ले जाने का आरोप लगा कर दो महिलाएं शहीद स्मारक पर धरने पर बैठ गईं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ दिनों पहले लापता बेटियों की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने गुमशुदी की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवाई है लेकिन आज तक पुलिस दोनों बेटियों को ढूँढ नहीं पाई है।

परेशान परिजनों ने सोमवार को शहीद स्मारक पर धरना देकर अपनी बेटियों का पता लगाने की गुहार सीएम से लगाई है।

कोतवाली थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी ने बताया की सूचना पर पहुंचे हैं यहां दो महिलाएं अपनी लापता बेटियों की तलाश के लिए धरने पर बैठी रहीं। मामले में पहले गुमशुदी दर्ज की हुई है लड़कियों का पता लगाया जा रहा है। दोनों महिलाओं को अश्वासन दिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उन्हें ढूँढ लिया जाएगा। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में शीघ्र ही तलाश कर लिया जायेगा।

राहुल की भारत जोड़े न्याय यात्रा दो से छह तक म.प्र. में, उज्जैन में होगा रोड शो

भोपाल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़े न्याय यात्रा मध्यप्रदेश में दो से छह मार्च तक आयोजित होगी, जिसकी शुरुआत मुरैना से होगी।

प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने बताया कि न्याय यात्रा दो मार्च को मुरैना से शुरू होगी। मुरैना में रोड शो एवं स्वागत कार्यक्रम होगा। मुरैना में ही श्री गांधी का संबोधन होगा।



मोहन यादव के बुलडोजर ने ढहा दिए 386 घर

भोपाल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रशासन का बुलडोजर ऐक्शन लगातार जारी है। भोपाल की भद्रभदा बस्ती में बुलडोजर चलाकर अब 300 से ज्यादा घरों को जमींदोज किया जा चुका है। बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण इस ऐक्शन की वजह भी सामने आई है। लगातार 5 दिनों तक हुई बुलडोजर कार्रवाई में प्रशासन ने सैकड़ों निगम कर्मचारियों और सैकड़ों की ही संख्या में पुलिस कर्मियों की सहायता भी ली।



क्यों जमींदोज किए गए 386 घर?

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की भद्रभदा बस्ती में 6 दिन पहले बुलडोजर ऐक्शन शुरू हुआ था। 5 दिन तक चले बुलडोजर ऐक्शन में अब तक 300 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने बताया कि ये सभी घर कैचमेंट एरिया में बने थे। प्रशासन ने बताया कि भद्रभदा बस्ती के जिन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं उनको सरकार ने दो विकल्प दिए हैं। या तो वो अपने तोड़े

जा रहे घर का मुआवजा ले लें या फिर सरकार द्वारा उनके आवास की व्यवस्था कर दी जाएगी। इनमें लोगों को विकल्प चुनने की आजादी है।

सैकड़ों पुलिसवालों ने संभाला मोर्चा

भोपाल की भद्रभदा बस्ती को लगभग नेस्तनाबूत कर दिया गया है। अब तक यहां के 386 घरों को तोड़ा जा चुका है। कैचमेंट एरिया में बने सभी घरों के मालिकों को विकल्पों को चुनने के लिए भी कहा गया है। इस दौरान किसी भी विरोध से निपटने के

लिए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया हुआ है। प्रशासन ने इलाके में स्थित संभालने के लिए 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 600 से ज्यादा निगम कर्मचारियों को तैनात कर रखा है।

भद्रभदा बस्ती में 3 दिनों के अंदर 261 मकानों पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया था। प्रशासन ने 125 और घरों पर कार्रवाई करने की बात कही थी। अब तक 300 से ज्यादा घरों को जमींदोज किया जा चुका है।

नौकरी चले जान के डर से परेशान पेटीएम के फील्ड मैनेजर ने दी जान, इंदौर में घर के अंदर लगाई फांसी

इंदौर। संकट के दौर से गुजर रही पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एक कथित फील्ड मैनेजर द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है।

शुरुआती जांच में पता चला है कि वह पिछले कुछ दिनों से अपनी जॉब चले जाने के डर से टेंशन में था। पुलिस ने मृतक कर्मचारी के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के 35 वर्षीय कर्मचारी ने इंदौर में कथित तौर पर फांसी लगाकर जान दे दी। अधिकारी ने शुरुआती जानकारी के हवाले से बताया कि पेटीएम कर्मचारी अपनी नौकरी खोने के डर से पिछले कुछ दिनों से दबाव में था।

लसूड़िया पुलिस थाने के प्रभारी तारेश कुमार सोनी ने बताया कि पेटीएम के कर्मचारी गैरव गुप्ता (35) ने अपने घर में रविवार को फांसी

लगाकर आत्महत्या कर ली। सोनी ने बताया, “हमें शुरुआती जानकारी मिली है कि गैरव गुप्ता इस आशंका के चलते दबाव में थे कि पेटीएम बंद हो



सकता है, जिससे उनकी जॉब चली जाएगी। हम इस संबंध में जांच कर रहे हैं।” थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस को गुप्ता का सुसाइड नोट नहीं मिला है और उनके शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है। उन्होंने बताया कि पेटीएम कर्मचारी की मौत के मामले की

विस्तृत जांच की जा रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी को आदेश जारी करते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) को 29 फरवरी के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रमेंट्स, वॉलेट, फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड में आगे जमा, लेनदेन या टॉप-अप रोकने के लिए कहा था। केंद्रीय बैंक ने इसकी समयसीमा अब बढ़ाकर 15 मार्च कर दी है।

गैरतलब है कि विजय शेखर शर्मा ने सोमवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बैंक के निदेशक मंडल का पुनर्गठन किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियमों का अनुपालन नहीं करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक तिल (पीपीबीएल) को 15 मार्च के बाद ग्राहकों से कोई भी नई जमा राशि या ‘टॉप अप’ स्वीकार करने से रोक दिया है।

स्मृति शेषमौन हुई अमीन सयानी की मीठी और मोहक आवाज

● संपादक की कलम से.....

अमीन सयानी हमारे जमाने के ऐसे अकेले रेडियो उद्घोषक थे जिन्हे देश उनकी शब्दकल से नहीं बल्कि आवाज से पहचानता था। अमीन सयानी ने अपने जीवन के 91 साल की यात्रा में से लगभग 60 साल तक देश की जनता को अपनी आवाज के जादू से बांधे रखा।

आज की पीढ़ी को शायद इस बात पर भरोसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति केवल अपनी आवाज की दम पर लोगों के दिलों-दिमाग पर छाया रह सकता है।

अमीन सयानी से मैं कभी मिला नहीं किन्तु मुझे और मेरे जैसे असंख्य लोगों को ये

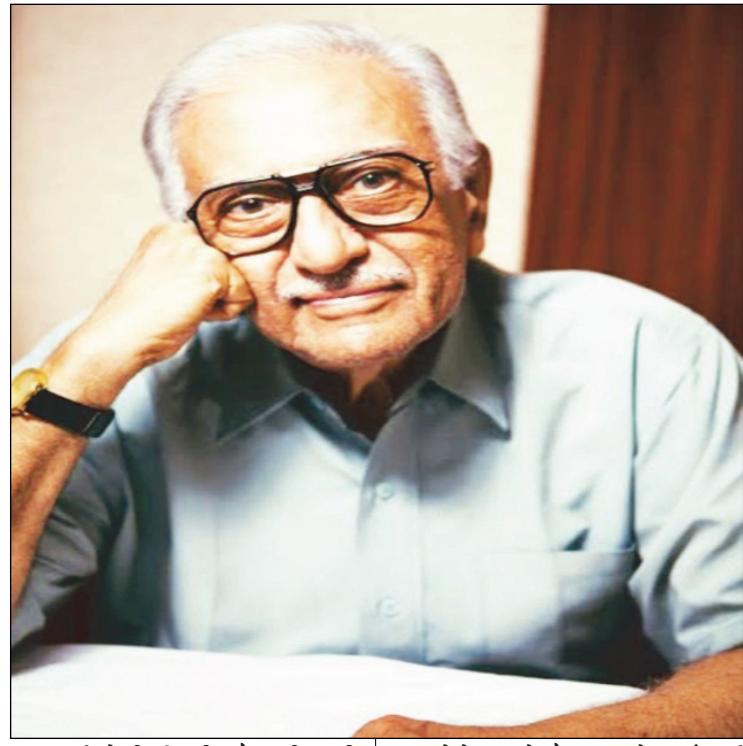
उद्घोषक के रूप में अमीन सयानी जाने जाते थे। वे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तरह अपनी आवाज के बूते पर जाने जाते थे।

आज हजारों टीवी चैनल हैं, रेडियो हैं लेकिन आप शायद ही किसी एक उद्घोषक को उसकी आवाज से पहचानते हों। आज उद्घोषकों की भीड़ है, उस जमाने में अमीन सयानी जैसे गिने-चुने उद्घोषक थे। रेडियो पर 'भाइयों और बहनों' के संबोधन के जरिए पहचाने जाने वाले सयानी

कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। ऑल इंडिया रेडियो को लोकप्रिय बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। अमीन सयानी ने कई फिल्मों में रेडियो अनाउंसर के तौर पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

मुझे याद है कि वे तीन देवियां, भूत बंगला और बॉक्सर फिल्म में एक उद्घोषक के रूप में ही नजर आये थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उन दिनों जब हम स्कूल में थे तब भी अमीन सयानी के शो 'बिनाका गीतमाला'

को सुनने के लिए रेडिओ से चिपके रहते थे। जिनके घरों पर रेडियो नहीं था वे बाजार में किसी पान वाले या किसी चाय वाले के यहां बजने वाले रेडियो के आसपास जमा



भाषा उर्दू बोली, लिखी और पढ़ी जाती थी। अमीन सयानी को उनके भाई हामिद सयानी ने उन्हें रेडियो से जोड़ा था। 10 साल तक वे इंग्लिश कार्यक्रम का हिस्सा रहे। आजादी के बाद उन्होंने हिंदी की ओर रुख किया।

खुद अमीन सयानी अपने बचपन में गुजराती बोलते थे। उनकी माँ गांधीजी की शिष्या थी। गांधी जी ने उनकी माँ को हिंदी, गुजराती और उर्दू में पत्रिका निकालने की सलाह दी थी। उनकी माँ ने ये काम अमीन सयानी को सौंपा और इससे भी उन्हें अपनी भाषाओं के विस्तार में काफी मदद मिली।

अमीन सयानी उन लोगों में से थे जिनकी नकल की जाती थी। महिला उद्घोषकों में उनका मुकाबला अक्सर तबस्सुम से हुआ करता था। लेकिन ऐसा उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। उन जैसे लोग सदी में कभी-कभी जन्म लेते हैं। मोहक आवाज और मधुर मुस्कान से भरे इस व्यक्तित्व को विनम्र श्रद्धांजलि।

साहब ने करीब 54 हजार रेडियो कार्यक्रम किए और 19 हजार स्पार्ट्स या जिंगल्स किए। इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकाइर्स में भी शामिल है।

बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य हासिल होता है कि वे जिस मिट्टी में पैदा हुए हों, उसी में उन्हें अंतिम साँस लेने का मौका भी मिले। अमीन सयानी ऐसे ही खुशनसीब लोगों में से एक थे। अमीन सयानी का जन्म 21 दिसंबर 1932 को मुंबई में हुआ था। देश में पहली रेडियो सेवा शुरू हुई तो अमीन सयानी एक उद्घोषक के रूप में उसमें भर्ती हो गए। सयानी साहब ने सन 1951 में रेडियो उद्घोषक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो मुंबई से की थी। अपनी आवाज के जादू से वे समां बांध देते थे। शुरुआत में उन्होंने अंग्रेजी

हो जाते थे। कस्बों में तो बिनाका गीतमाला के फिल्मी गीत सुनने के लिए जाम की स्थिति बन जाती थी। उस जमाने में केवल बिनाका गीतमाला सुनने के लिए रेडियो खरीदने का चलन था और इसका श्रेय था अमीन सयानी साहब की आवाज को।

अच्छी और सुरीली आवाज के लोग प्रायः गायक बनना चाहते हैं। कहते हैं कि अमीन सयानी भी एक गायक बनना चाहते थे लेकिन गायक बनना उनके नसीब में नहीं था। उन्हें तो एक कामयाब रेडियो उद्घोषक बनने के लिए पैदा किया गया था। वे मानते थे कि अच्छी हिंदी बोलने के लिए थोड़ा-सा उर्दू का ज्ञान होना आवश्यक है। उनका परिवार बहुभाषी था इसका लाभ उन्हें मिला। उनके यहां हिंदी, अंग्रेजी के अलावा उनकी अपनी मातृ

प्रतिकल्पा के कलाकारों ने दी पारम्परिक कलाओं की प्रस्तुति

उज्जैन। श्रीमंत राजमाता विजयराजे सिंधिया फाउण्डेशन, भारत एवं अटल भारत क्रीड़ा एवं कला संघ, भारत द्वारा कला के क्षेत्र में निरंतर अनुशासित कार्य करते हुए नित नए आयाम रख कर उज्जयिनी का नाम गौरवान्वित करने वाली डॉ. पल्लवी किशन को शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में अटल अवार्ड से सम्मानित किया गया।

प्रतिकल्पा संस्था के सचिव कुमार राजकीय किशन ने बताया कि कालिदास अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुकेश टट्टवाल महापौर, राजेंद्र भारती पूर्व

विधायक, चित्रेश शर्मा, राजशेखर व्यास, महेश गोयल उपस्थित थे। इस

स्वधा चतुर्वेदी, ईशान्वी राठौर, रिद्धिमा खड़ेलवाल, भुवनेशी समाधिया, निष्ठा शर्मा, सुति शर्मा, कावेरी कश्यप, आस्था मेहर शामिल थीं।

इस अवसर पर प्रतिकल्पा परिवार एवं उज्जैन के अनेक वरिष्ठ कलाकारों द्वारा डॉ. पल्लवी किशन को प्राप्त इस उपलब्धि के लिए बधाई प्रेषित की। उक्त आयोजन में देशभर के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कला, खेल, चिकित्सा एवं रक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को अटल अवार्ड से विभूषित किया गया।

